



SHRI MUZAFFAR HUSSAIN BAIG

Shri Muzaffar Hussain Baig is an eminent politician from Jammu & Kashmir.

2. Born on 8th May, 1946, Shri Baig has to his credit many firsts in his academic journey like first in order of merit in the provincial middle standard examination, Kashmir; First position in order of merit in higher secondary (core) examination in Kashmir province; first in order of merit in Bachelor Arts examination from Kashmir University; first in order of merit in LLB examination from Delhi University. He received a gold medal and three certificates of excellent record from the then Vice President of India who presided over the university convocation function.

3. Shri Baig started practice of law in 1972 simultaneously, he was appointed lecturer of law in Kashmir University. In 1974, he obtained LLM degree from Harvard Law School, and in 1975 practised law in San Francisco and then in New York from 1975 to 1979. He returned to Kashmir and was elected Vice Chairman of People's Conference. From 1985-88, he functioned as Advocate General of Jammu and Kashmir. He started private practice in Supreme Court and various High courts of India from 1989. He was the first lawyer in Jammu and Kashmir who was designated as senior advocate in 1989.

4. Shri Baig contested Parliament elections in 1979 and 1984. He became a Cabinet Minister in Jammu and Kashmir Government in 2002 and held portfolio of Finance, Planning, Law and Parliamentary Affair, Ladakh Affairs and Tourism at a later stage. He became Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir in 2005 and was elected Member of Legislative Assembly in 2008 and a Member of Parliament in 2014. As Advocate General, he drafted and, later in court, defended Mata Vaishno Devi Act. Later, as Minister of Law, on the model of Mata Vaishno Devi Act, he got a similar law passed relating to specified Muslim Wakf properties. He also got a special Law passed relating to monitoring of consumption of electricity to check its theft and misuse by consumers.

5. As Finance Minister of Jammu and Kashmir, Shri Baig introduced the Practice of Zero Fiscal Deficit Budget. As Planning Minister, he obtained loan from IMF for special projects in Kashmir and to implement these projects he setup an Economic Reconstruction Agency in the State of which he became the chairman to monitor its activities and achievement of development projects. He also functioned as Vice-President, President and Chief Patron of Peoples Democratic Party at different times.

6. Shri Baig has received various honours and awards including "Bharat Gaurav Award" in 2005.





श्री मुज़फ्फर हुसैन बेग

श्री मुज़फ्फर हुसैन बेग जम्मू और कश्मीर के एक प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ हैं।

2. 8 मई, 1946 को जन्मे श्री बेग को अपने शैक्षणिक काल में कई बार प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है, जैसे कि उन्होंने कश्मीर की प्रांतीय मध्य स्तर परीक्षा में मेरिट–क्रम में प्रथम स्थान; कश्मीर प्रांत में उच्च माध्यमिक (कोर) परीक्षा में मेरिट–क्रम में प्रथम स्थान; कश्मीर विश्वविद्यालय की कला स्नातक परीक्षा में मेरिट–क्रम में प्रथम स्थान; दिल्ली विश्वविद्यालय की एलएलबी परीक्षा में मेरिट–क्रम में प्रथम स्थान हासिल किया। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति, जिन्होंने विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की थी, द्वारा उन्हें उत्कृष्ट रिकॉर्ड के लिए एक स्वर्ण पदक और तीन प्रमाणपत्र प्रदान किए।

3. श्री बेग ने 1972 में कानून की प्रैक्टिस शुरू की और साथ ही साथ उन्हें वे कश्मीर विश्वविद्यालय में लेक्चरर ऑफ लॉ के पद पर भी नियुक्त किया गया। वर्ष 1974 में, उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम की डिग्री प्राप्त की और 1975 में सैन फ्रांसिस्को में कानून की प्रैक्टिस की तथा 1975 से 1979 तक न्यूयॉर्क में कानून की प्रैक्टिस की। श्री बेग कश्मीर लौट आए और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष चुने गए। 1985–88 तक, उन्होंने जम्मू–कश्मीर के महाधिवक्ता के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1989 से उच्चतम न्यायालय और भारत के विभिन्न उच्च न्यायालयों में निजी प्रैक्टिस की शुरुआत की। वह जम्मू–कश्मीर से आने वाले पहले वकील थे जिन्हें 1989 में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित किया गया था।

4. श्री बेग ने 1979 और 1984 में संसद का चुनाव लड़ा। वह वर्ष 2002 में जम्मू–कश्मीर सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और वित्त, योजना, कानून और संसदीय कार्य मंत्री का कार्यभार संभाला तथा बाद में लद्दाख मामलों के मंत्री और पर्यटन मंत्री भी बने। वे वर्ष 2005 में जम्मू और कश्मीर के उप मुख्यमंत्री बने और वर्ष 2008 में विधान सभा के सदस्य और वर्ष 2014 में संसद सदस्य चुने गए। महाधिवक्ता के रूप में, श्री बेग ने माता वैष्णो देवी अधिनियम का मसौदा तैयार किया और बाद में न्यायालय में उसकी वकालत भी की। बाद में, कानून मंत्री के रूप में, माता वैष्णो देवी अधिनियम की तर्ज पर, उन्होंने खासतौर मुस्लिम वक्फ संपत्तियों से संबंधित एक कानून पास कराया। उन्होंने उपभोक्ताओं द्वारा बिजली चोरी और उसके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए बिजली की खपत की निगरानी से संबंधित एक विशेष कानून भी पारित करवाया।

5. जम्मू–कश्मीर के वित्त मंत्री के रूप में, श्री बेग ने जीरो फिस्कल डेफिसिट बजट की व्यवस्था शुरू की। योजना मंत्री के रूप में, उन्होंने कश्मीर में विशेष परियोजनाओं के लिए आईएमएफ से ऋण प्राप्त किया और इन परियोजनाओं को लागू करने के लिए उन्होंने राज्य में एक आर्थिक पुनर्निर्माण एजेंसी स्थापित की, तथा इसकी गतिविधियों एवं विकास परियोजनाओं की उपलब्धियों की निगरानी करने के लिए इसके अध्यक्ष बने। उन्होंने अलग–अलग समय में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और मुख्य संरक्षक के रूप में भी काम किया।

6. श्री बेग को 2005 में "भारत गौरव पुरस्कार" सहित विभिन्न सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।